RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 200
दि. 21.11.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

बिहार में एनडीए की सरकार, नीतीश बने 10वीं बार बिहार के सीएम

(जीएनएस)।

पटना, बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन हो गया है जिसमें नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें बीजेपी के 14 और जदयू के 8 मंत्री शामिल हैं. नए मंत्रियों में एक मुस्लिम, तीन महिलाएं और तीन नए विधायक भी शामिल हैं.

बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन हो गया है. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जनता दल (यूनाइटेड) के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

नीतीश कुमार के साथ उनकी नई कैबिनेट के 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली. इनमें बीजेपी के 14 और जदयू कोटे के 8 मंत्री शामिल हैं. 26 नए मंत्रियों में एक मुस्लिम, 3 महिलाएं शामिल हैं. वहीं, पहली बार विधानसभा पहुंचे 3 विधायक भी मंत्री बने हैं. समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, गुजरात के भूपेंद्र पटेल समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे.

गांधी मैदान में गूंजा बिहार में फिर नीतीश का नारा

गांधी मैदान को पूरी तरह सजाया-संवारा गया था. हजारों की संख्या में

जदयू-भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग समारोह में शामिल हुए. मंच पर 'बिहार में फिर एक बार- नीतीश कुमार' के नारे गूंजते रहे.

26 मंत्रियों ने ली शपथ

गांधी मैदान में नीतीश के अलावा गांधी मैदान में एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम के रूप में मंत्री पद की शपथ ली. सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा बीजेपी के मंगल पांडेय, डॉ. दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, डॉ . प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने भी बिहार सरकार मंत्री पद की शपथ ग्रहण की.

शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से भी आठ मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है. जेडीयू की से मंत्री पद की शपथ लेने वालों में विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मो. जमा खान, मदन सहनी, डॉ. प्रमोद कुमार का नाम शामिल है.

इसके अलावा चिराग की पार्टी से संजय कुमार (पासवान), संजय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की. उधर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से संतोष कुमार सुमन और दीपक प्रकाश ने भी नई सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली है.

10वीं बार सीएम बने नीतीश

बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो चुका है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है. नीतीश ने पहली बार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद 2010, 2015 (दो बार), 2017, 2020, 2022 (दो बार) और 2024 में शपथ ली थी. अब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना 10वां कार्यकाल शुरू कर दिया है. वह बिहार के अब तक सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं.

एनडीए की शानदार वापसी

बता दें कि बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है. एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 35 सीटों पर सीट हासिल की है.

राष्ट्रपति ने अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में 'जनजातीय गौरव दिवस' समारोह में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (20 नवंबर, 2025) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, सरगुजा में आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों का योगदान भारत के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है, जो लोकतंत्र की जननी है। इसके उदाहरण प्राचीन गणराज्यों के साथ-साथ कई जनजातीय परंपराओं में भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि बस्तर में 'मुरिया दरबार' - जो आदिम लोगों की संसद है।

राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय विरासत की जड़ें छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में गहरी हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़े को बड़े स्तर पर मनाया।

राष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि पिछले एक दशक में, जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएँ विकसित और कार्यान्वित की गई हैं। पिछले वर्ष, गांधी जयंती के अवसर पर 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' शुरू किया गया था। इस अभियान का लाभ देश भर के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई-बहनों तक पहुँचेगा। वर्ष 2023 में, 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन अभियान) शुरू किया गया। ये सभी योजनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार जनजातीय समुदायों को कितनी प्राथमिकता देती है।

प्रधानमंत्री ने बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं और कई वर्षों से सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने उन्हें नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा को बिहार के उप-मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के पास जनसेवा का लंबा अनुभव है और उन्होंने जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से काम किया है।

योगी आदित्यनाथ के पटना एयरपोर्ट पर निकलते ही लगे 'जय श्रीराम' के नारे, नीतीश को यूपी सीएम ने दी बधाई

(जीएनएस)।

लखनऊः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जबर्दस्त सफलता के बाद नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार के गठन के अवसर पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुरुवार को पटना पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे ही उनका विमान पटना एयरपोर्ट पर उतरा, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरा एयरपोर्ट परिसर 'जय श्रीराम' के नारों से गूंज उठा। सीएम योगी ने बिहार चुनाव में जमकर प्रचार किया था। भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को जीत दिलाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई।

पटना एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकताओं का अद्भुत उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए, लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। समर्थकों ने हाथ हिलाकर, नारे लगाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कई युवा और स्थानीय लोग एयरपोर्ट पर

पहुंचकर उनके प्रति अपना समर्थन और उत्साह जताते दिखे। यह नजारा इस बात का प्रतीक था कि बिहार की राजनीति में भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर का एक और महत्वपूर्ण अध्याय लिखते हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह अवसर एनडीए गठबंधन के लिए भी मजबूती का संदेश रहा। शपथ समारोह में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा और जदयू के वरिष्ठ नेता की उपस्थिति ने यह संकेत दिया कि बिहार में नई सरकार के साथ केंद्र और अन्य राज्य भी मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद

मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह भी शामिल हुए। केशव मौर्य को भाजपा ने बिहार चुनाव में सह प्रभारी बनाया था। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने एनडीए गठबंधन के लिए लगातार चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने कई जिलों में बड़ी जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में मजबूत माहौल तैयार किया।

उनकी खास शैली, प्रभावशाली वक्तव्य, जनता से आत्मीय संवाद, सांस्कृतिक और सुरक्षा आधारित संदेश ने बिहार के मतदाताओं पर गहरा प्रभाव छोड़ा। भाजपा संगठन में भी उनकी सक्रियता ने ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। सीएम योगी ने सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक पहचान पर स्पष्ट संदेश दिया था।

चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे 'विकसित भारत' अभियान को प्रमुखता से जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा, तेज विकास, सुशासन और सांस्कृतिक पहचान बिहार जैसे राज्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जनता से मिले समर्थन ने इन संदेशों की प्रभावशीलता को सिद्ध किया।

रिश्तों में नई मजबूती का संकेत

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी की उपस्थिति केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक, सामाजिक और विकासात्मक संबंधों के गहरे होने का प्रतीक मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार सांस्कृतिक रूप से जुड़वां राज्य हैं। दोनों राज्य साझा इतिहास, समान सामाजिक संरचना, आर्थिक और धार्मिक संबंध रखते हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक मंच पर आना आने वाले दिनों में सहयोग और विकास के नए रास्ते खोल सकता है।

भारत और जर्मनी ने बर्लिन में वैकल्पिक दवाओं पर तीसरे संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक में पारम्परिक दवाओं पर सहयोग को आगे बढ़ाया

पारम्परिक दवाओं के लिए एकीकरण, प्रतिपूर्ति के तरीकों और विनियामकीय तंत्र पर सहयोग को मजबूती मिलेगी

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और फेडरल स्वास्थ्य मंत्रालय, जर्मनी के बीच वैकल्पिक दवाओं पर तीसरे संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 18 से 20 नवंबर 2025 तक बर्लिन में हुई, जो पारम्परिक और एकीकृत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत-जर्मनी सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल को आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिशा दास ने अगुआई की और इसमें सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. (डॉ.) रविनारायण आचार्य; सीसीआरएच के डायरेक्टर जनरल डॉ. सुभाष कौशिक; आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉ. कौस्तभ उपाध्याय; और एमडीएनवाई के निदेशक डॉ. काशीनाथ समागंडी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने सहयोग के ठोस रास्ते तलाशने के लिए जर्मनी के बड़े संस्थानों से बातचीत की। कार्यक्रम की अगुआई करने वाले जर्मनी के अधिकारियों में पॉल जुबेइल, हेड ऑफ डिवीजन यूरोपियन एंड इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी, जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्रोफेसर डॉ. मेड. जॉर्ज सीफर्ट, हेड ऑफ कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ट्रेडिशनल एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, चैरिटे बर्लिन, एंड्रिया गैले, सीईओ, बीकेके एमकेके (स्टैच्युटरी हेल्थ इंश्योरेंस फंड), डॉ. जैकलीन विस्नर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर विटामिन्स,

मिनरल्स, स्पेशल थेराप्यूटिक अप्रोच, फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेज (बीएफएआरएम) शामिल थे।

चर्चा तीन खास बातों पर केंद्रित थी- पारंपरिक दवा को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करना, मरीजों तक पहुंच के लिए प्रतिपूर्ति के रास्ते बनाना और विनियामकीय मंजूरी प्रणाली को मजबूत करना। इन विषयों से प्रमाणों पर आधारित और लोगों पर केंद्रित पारंपरिक दवा के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का पता चलता है।

इस दौरे के खास कामों में शामिल थेः

कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ट्रेडिशनल एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, चैरिटे यूनिवर्सिटी, मिलकर रिसर्च के मौके तलाशने और आयुष मंत्रालय के साथ प्रस्तावित एमओयू को आगे बढ़ाना।

कम्युनिटी हॉस्पिटल हैवेलहोहे - एंथ्रोपोसोफिक मेडिसिन के लिए क्लिनिक, इंटीग्रेटिव केयर और रिसर्च के तरीकों की समीक्षा करेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने टेक्नोलॉजी के उपयोग से ऑनलाइन जन शिकायत निवारण के कार्यक्रम 'स्वागत' में उपस्थित रहकर शिकायतों के निवारण का मार्गदर्शन दिया

गांधीनगर, 20 नवंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित नवंबर महीने के राज्य स्तरीय 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में प्रस्तुत शिकायतों और समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि लोगों की समस्याओं और शिकायतों को गहराई से समझते हुए तथा जमीन पर जाकर उनका शीघ्र निवारण करना आवश्यक है।

बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2003 में शुरू किया गया राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष पहुंचाने के साथ ही समस्या के निवारण से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों की समस्याओं को हमेशा प्राथमिकता देकर उनके त्वरित निवारण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, इसकी मिसाल नवंबर महीने के राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में देखने को मिली।

इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में 70 से अधिक नागरिक अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने के लिए आए थे, जिनमें से 4 आवेदकों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर सुना। जबकि शेष समस्याओं को मुख्यमंत्री जनसंपर्क इकाई के अधिकारियों ने सुना और कार्रवाई के लिए संबद्ध विभागों तथा जिला स्तर के अधिकारियों को भेजा।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित नवंबर महीने के जिला 'स्वागत' के तहत प्राप्त 1156 शिकायतों की निराकरण कार्यवाही जिला स्तर पर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर तहसील और जिला 'स्वागत' की शिकायतों के संबंध में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन और उनकी गहन निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जिन तहसीलों और जिलों में लंबित शिकायतों की संख्या अधिक है, ऐसे जिलों में शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के दिशानिर्देश भी दिए।

पोरबंदर जिले के दो गांवों के किसानों ने सुखभादर नदी पर पुल बनाने की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर राज्य 'स्वागत' में मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने उन किसानों के प्रति संवेदना दशार्ते हुए इस पुल को मंजूरी देने के लिए सड़क एवं भवन विभाग के सचिव को त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया।

सम्पादकीय

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं और युवाओं के बड़े हिस्से का समर्थन एनडीए को मिला

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने राज्य की राजनीति और सामाजिक समीकरणों पर बड़ा प्रभाव डाला है। इस बार बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन रिकॉर्ड सीटों के साथ भारी बहुमत से सत्ता में लौट रहा है, जबकि महागठबंधन (राजद-कांग्रेस गठबंधन) को गंभीर झटका लगा है। चुनाव परिणाम के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि एनडीए ने 243 में से 200 से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित की है, जिसमें बीजेपी को 91, जेडीयू को 81 एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 21 सीटें मिली हैं। वहीं, विपक्षी महागठबंधन महज 38 सीटों पर सिमट गया है, जिसमें राजद 26, कांग्रेस 4 और वामदल (सीपीआई, सीपीएम आदि) 6 सीटों पर आगे दिखे। ये आंकड़े अनंतिम हैं। इसमें मामूली बदलाव सम्भाव्य है। मतदाता प्रतिशत 66.91% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, महिलाएं 71.6% की हिस्सेदारी के साथ निर्णायक भूमिका में रहीं। इन नतीजों के मायने दिलचस्प हैं- पहला, शासन और नेतृत्व पर असरः चुनाव परिणाम ने "डबल इंजन" की सरकार यानी केंद्र-राज्य एक ही साझा गठबंधन के फॉर्मूले पर जनता की मुहर को मजबूती दी है। इससे राज्य में स्थिरता, नीति निरंतरता तथा केंद्र से सहयोग की उम्मीद है। एनडीए में बीजेपी की सीट्स जेडीयू से अधिक हैं, जिससे भाजपा का राज्य के सत्ता-समीकरण, मंत्रिमंडल गठन और नीतियों पर कड़ा प्रभाव होगा। इसे भी पढ़ें: बिहार चुनाव से पहले राहुल का 'वोट चोरी' दांव: क्या जेन-ज़ी को भड़काने की साजिश? दूसरा, विपक्ष के लिए संदेश: राजद और महागठबंधन की हार, खासकर युवा व महिला वोटर्स के बड़ी संख्या में एनडीए की ओर जाने के कारण हुई है, जिससे विपक्षी वृत्तियों को खुद की रणनीति और नेतृत्व की समीक्षा करनी होगी। तीसरा, सामाजिक-राजनीतिक पटल पर प्रभावः वोटर टर्नआउट में नई ऊंचाई और महिला वोटर्स का रुझान, सामाजिक विकास, शिक्षा-स्वास्थ्य, सुरक्षा के मुद्दों को आगे लाता है; वहीं जाति-आधारित राजनीति कुछ हद तक कमजोर होती दिखी। वहीं, छोटे दलों की भूमिका बनी रही, जिससे स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रों के लिए बैलेंसिंग एक्ट की आवश्यकता बढ़ गई है। चतुर्थ, राष्ट्रीय राजनीति के लिए संकेत: बिहार का परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मनोबल और संदेश देता है कि क्षेत्रीय गठबंधन नीति और विकास एजेंडा कारगर है। वहीं, एक सवाल यह भी है कि बिहार परिणाम का राष्ट्रीय राजनीति पर असर क्या होगा? तो जवाब होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की भारी जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर कई स्तरों पर असर पड़ेगा। बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन की सफलता विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कमजोर करती है, जबकि एनडीए की नीतियों और नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलती है। राष्ट्रीय राजनीति का नया समीकरणः एनडीए की जीत से प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व की लोक-प्रियता को बड़ा सहारा मिला है। इससे भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव 2029 और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में रहेगी। बिहार के नतीजे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एनडीए के लिए गति और उदाहरण बनेंगे। वहीं, विपक्षी इंडिया गठबंधन में अंदरूनी फूट, नेतृत्व संकट और जमीनी कमजोरियां उजागर हुई हैं। कमजोर प्रदर्शन से विपक्षी गठबंधन के भविष्य, नेतृत्व और संयुक्त रणनीति को लेकर गंभीर सवाल पैदा होंगे। साथ ही, ममता बनर्जी (प. बंगाल), अखिलेश यादव (यूपी) जैसे क्षेत्रीय नेताओं के लिए भी बिहार का परिणाम मार्गदर्शक होगा कि उन्हें अपनी गठबंधन संरचना पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। नीतिगत और सामाजिक प्रभावः बिहार में एनडीए की सरकार के विकास-कार्य, स्वास्थ्य-शिक्षा और महिला-सशक्तिकरण एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राथमिकता पा सकता है। वहीं, महिलाओं और युवाओं के बड़े हिस्से का समर्थन एनडीए को मिला, इससे सामाजिक सुधार और चुनावी रणनीति में इन वर्गों का महत्व बढ़ेगा। वहीं, भाजपा और जेडीयू में सीटों के समीकरण से भी केंद्रीय सत्ता में गठबंधन के आंतरिक समीकरण बदल सकते हैं।

कच्छ और सौराष्ट्र के लिए नए निवेश और औद्योगिक अवसरों के द्वार खोलेगा आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस

- कच्छ और सौराष्ट्र में तेजी से उभरते औद्योगिक एवं निवेश अवसर
- मोरबी, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, द्वारका और भावनगर पश्चिमी गुजरात के प्रमुख ग्रोथ हब
- द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसः 8-9 जनवरी 2026 को राजकोट में

गांधीनगर,20 नवंबर :गुजरात सरकार कच्छ और सौराष्ट्र के समग्र विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। यह सम्मेलन इन दोनों क्षेत्रों में उभर रहे औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवसरों को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। साथ ही, यह पश्चिमी गुजरात में तेजी से बढ़ते निवेश, नए अवसरों और समावेशी विकास की गति को भी रेखांकित करेगा।

क्षेत्रीय विकास के प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस

सम्मेलन में सेरामिक्स, इंजीनियरिंग, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स, मत्स्य उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग, खनिज, ग्रीन एनर्जी, कौशल विकास, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, पर्यटन और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष चर्चाएं होंगी। रणनीतिक साझेदारियों, नीतिगत प्रोत्साहनों और निवेशकों की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से यह आयोजन पश्चिमी पट्टी में सतत औद्योगिक विस्तार और संतुलित विकास को गति देने का उद्देश्य रखता है।

कच्छ से मोरबी और जामनगर तकः पश्चिमी गुजरात में उभरते नए निवेश केंद्र

कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला, विकसित अवसंरचना, मजबूत बंदरगाह कनेक्टिविटी और विस्तार पाते औद्योगिक गलियारों के कारण आज वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। कांडला और मुंद्रा जैसे देश के महत्त्वपूर्ण पोर्ट इसकी आर्थिक क्षमता को और मजबूती देते हैं। पशुपालन, विविध पर्यटन स्थलों और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों ने कच्छ को पेट्रोकेमिकल्स, 32 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और एग्रो प्रोसेसिंग के लिए अत्यंत आकर्षक निवेश गंतव्य बना दिया है।

मोरबी, जिसे देशभर में सिरेमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यह 900 से अधिक विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से सिरेमिक उद्योग में गुजरात की नेतृत्वकारी भूमिका को स्थापित करता है। यह जिला घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में उल्लेखनीय योगदान देता है।

जामनगर, अपनी सशक्त औद्योगिक पहचान के साथ ब्रास सिटी ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ 15,000 से अधिक इकाइयाँ पीतल के महत्वपूर्ण उत्पादों का निर्माण करती हैं। आम, अमरूद और अनार जैसे उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के उत्पादन ने इसे एग्रो-आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया है। जामनगर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इसकी वैश्विक औद्योगिक क्षमता को और बढ़ाती है।

राजकोट से तटीय जिलों तकः उद्योग, संस्कृति और व्यापार का मजबूत संगम

राजकोट, गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा जिला, देश के मशीन टूल्स और विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी है। टरटए विकास, नवीन उद्यमिता और बांधणी-अजरख जैसी पारंपरिक कलाओं ने इसे औद्योगिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनाया है।

पोरबंदर, महात्मा गांधी की जन्मभूमि, मत्स्य उद्योग, मिनरल प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प तथा देश के सबसे बड़े कॉस्टिक सोडा प्लांट के कारण औद्योगिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र केमिकल्स जैसी संस्थाएँ इस क्षेत्र के औद्योगिक तंत्र को मजबूती देती हैं।

देवभूमि द्वारका, भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी पावन भूमि होने के साथ-साथ औद्योगिक रूप से भी उल्लेखनीय है। मिथापुर स्थित टाटा केमिकल्स का संयंत्र देश के प्रमुख सोडा ऐश उत्पादकों में शामिल है, जबकि ओखा बंदरगाह मछली उत्पादों, खनिजों और नमक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निर्णायक भूमिका निभाता है।

भावनगर, प्याज उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र होने के अलावा अलंग में स्थित विश्व के सबसे बड़े शिप-ब्रेकिंग यार्ड के कारण वैश्विक समुद्री उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बोटाद एक उभरता हुआ औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। सुरेंद्रनगर, कपास, सौंफ और नमक उत्पादन में अग्रणी होने के साथ-साथ बंधनी और टांगलिया बुनाई की समृद्ध परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है।

जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में कृषि और एग्रो-प्रोसेसिंग उद्योगों के साथ-साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिरनार पर्वत जैसी पर्यटन संपदाएँ इन्हें इको-टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग के नए अवसरों से जोड़ती हैं। अमरेली, जहां देश का पहला निजी क्षेत्र का पिपावाव पोर्ट स्थित है, यह थोक व कंटेनर कार्गो के लिए प्रमुख समुद्री द्वार है। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग तथा सीमेंट उद्योग ने अमरेली को सौराष्ट्र की औद्योगिक विविधता में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है।

8 और 9 जनवरी 2026 को राजकोट में आयोजित होगा द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस

राजकोट में आयोजित होने वाली आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस गुजरात सरकार की क्षेत्रीय प्रगति को अगले चरण में ले जाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सतत औद्योगिक इकोसिस्टम, कौशल विकास और नवाचार पर विशेष फोकस के साथ कच्छ और सौराष्ट्र 'विकसित गुजरात-विकसित भारत @2047' की परिकल्पना को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे

पीएम ने कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में किसानों के साथ बातचीत की

कृषि, नवाचार और स्थिरता की दिशा में किसानों का जुनून उल्लेखनीय है: प्रधानमंत्री

धान के क्षेत्र में तमिलनाडु द्वारा किया गया कार्य विश्व स्तर पर बेजोड़ है: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ गाँवों और कुशल पशुधन देखभाल के लिए गुजरात की 'कैटल हॉस्टल' अवधारणा का उल्लेख किया

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में किसानों से बातचीत की। श्री मोदी ने प्राकृतिक खेती में लगे किसानों का अभिवादन करते हुए केले की उपज का अवलोकन किया और केले के अवशेषों के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। किसान ने बताया कि प्रदर्शित सभी वस्तुएँ केले के अवशेषों से बने मूल्यवर्धित उत्पाद हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या उनके उत्पाद पूरे भारत में ऑनलाइन बेचे जाते हैं, इस के उत्तर में किसान ने पुष्टि की। किसान ने आगे बताया कि वे किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं के माध्यम से पूरे

तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके उत्पाद ऑनलाइन बेचे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं और पूरे भारत में स्थानीय बाजारों और सुपरमार्केट में भी उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने पूछा कि प्रत्येक एफपीओ में कितने लोग एक साथ काम करते हैं, तो किसान ने उत्तर दिया कि लगभग एक हजार लोग इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया और आगे पूछा कि क्या केले की खेती केवल एक ही क्षेत्र में की जाती है या अन्य फसलों के साथ मिश्रित की जाती है। किसान ने स्पष्ट किया कि विभिन्न क्षेत्र अलग-अलग विशिष्ट उत्पादों में विशेषज्ञता रखते हैं और उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास जीआई उत्पाद भी हैं।

एक अन्य किसान ने बताया कि चाय की चार किस्में हैं- काली चाय, सफेद चाय, ऊलोंग चाय और हरी चाय। उन्होंने विस्तार से बताया कि ऊलोंग चाय 40 प्रतिशत किण्वित होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन दिनों सफेद चाय का एक महत्वपूर्ण बाजार है, जिस पर किसान सहमत हुए। किसानों ने विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों जैसे बैंगन और आम को भी प्रदर्शित किया जो विभिन्न मौसमों में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए जाते हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फिर मोरिंगा या ड्रमस्टिक की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या इस उत्पाद की वर्तमान में बाजार में मजबूत उपस्थिति है, जिस पर किसान ने सकारात्मक जवाब दिया। श्री मोदी ने इसकी पत्तियों के उपयोग के बारे में पूछा, जिस पर किसान ने बताया कि मोरिंगा की पत्तियों को पाउडर में संसाधित किया जाता है और निर्यात किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों मोरिंगा पाउडर की काफी मांग है।

इसके उत्तर में किसान ने बताया कि पूरे प्रदर्शन में तमिलनाडु के जीआई उत्पाद शामिल थे, जिसमें कुंभकोणम के पान के पत्ते और मदुरै की चमेली सहित 25 वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। श्री मोदी ने बाजार पहुंच के बारे में पूछा, जिस पर किसान ने जवाब दिया कि ये उत्पाद पूरे भारत में उपलब्ध हैं और तमिलनाडु में हर समारोह के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या वाराणसी के लोग भी पान के पत्ते प्राप्त करते हैं, जिस पर किसान ने सकारात्मक रूप से पुष्टि की।

श्री मोदी ने उत्पादन में वृद्धि के बारे में पूछा, जिस पर किसान ने जवाब दिया कि उनके पास वर्तमान में 100 से अधिक उत्पाद हैं, जिनमें शहद एक प्रमुख वस्तु है। प्रधानमंत्री ने बाजार क्षमता के बारे में पूछताछ की और किसान ने पुष्टि की कि मांग बहुत अधिक है और उनके शहद उत्पाद वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहे हैं।

प्रधानमंत्री को आगे बताया गया कि उनके पास लगभग एक हजार पारंपरिक धान की किस्में हैं, जिनका पोषण मूल्य मोटा अनाज के बराबर है। श्री मोदी ने कहा कि धान के क्षेत्र में तमिलनाडु द्वारा किया गया कार्य वैश्विक स्तर पर बेजोड़ है। किसान ने इस बात पर सहमति जताते हुए इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा कि निर्यात किए जा रहे सभी धान, चावल और संबंधित मूल्यवर्धित उत्पादों को आयोजन स्थल पर प्रदर्शित किया गया है।

राष्ट्रीय योजना समूह की 102वीं बैठक में पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की गई

एनपीजी ने रेलवे, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र की तीन प्रमुख परियोजनाओं का मूल्यांकन किया

(जीएनएस)। सड़क परिवहन एवं राजमार्गों की अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए आज राष्ट्रीय योजना समूह (एनपीजी) की 102वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) के अनुरूप मल्टीमॉडल संपर्क एवं रसद दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एनपीजी ने तीन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया, जिनमें से एक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सड़क/हाईवे परियोजनाएं और दो रेलवे की परियोजनाएं थीं जिसका उद्देश्य यह देखना था कि वे पीएम गति शक्ति के एकीकृत मल्टीमॉडल अवसंरचना, आर्थिक एवं सामाजिक केंद्रों तक अंतिम-मील संपर्क एवं 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण के सिद्धांतों के अनुरूप हैं या नहीं। इन पहलों से रसद की दक्षता बढ़ने, यात्रा समय कम होने और परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुमानित प्रभाव निम्नलिखित हैं:

पुनारख से किऊल स्टेशन (बिहार) के बीच तीसरी और चौथी लाइनः रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य में पुनारख और किऊल स्टेशनों के बीच लगभग 49.57 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित खंड पटना और लखीसराय जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य के प्रमुख औद्योगिक एवं कृषि गलियारों में रेल अवसंरचना मजबूत होगी।

यह कॉरिडोर सामरिक एवं आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, एससी सीमेंट (वारसलीगंज),

एनटीपीसी बरौनी, एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर संयंत्र (बाढ़), कैरिज रिपेयर वर्कशॉप (हरनौत) और एसजेवीएन उर्जा संयंत्र (चौसा) सहित प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रेल क्षमता एवं रसद दक्षता में वृद्धि करेगा। इससे फतुहा, पटना-पाटलिपुत्र, मोकामा, बड़हिया और लखीसराय में ऑटोमोबाइल, मार्बल, पत्थर, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम और कपड़ा उत्पादन में शामिल कई लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी लाभ प्राप्त होगा।

इस परियोजना से बिहार तथा देश के अन्य हिस्सों के लिए तेज, सुरक्षित एवं निर्बाध रेल संपर्क प्राप्त होगा जिससे आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। बेहतर पहुंच से विशेष रूप से पटना, फतुहा, बख्तियारपुर और मोकामा जैसे केंद्रों को लाभ होगा, जिससे यात्री एवं माल ढुलाई दोनों में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, प्रस्तावित रेलवे लाइन बापू टॉवर, महावीर मंदिर, गांधी संग्रहालय, खुदा बख्श लाइब्रेरी, कुम्हरार, पटना साहिब, गोल घर और बिहार संग्रहालय सहित कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक संपर्क में सुधार लाएगा, जिससे पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।

सिलघाट (सिलघाट टाउन) से देकारगांव (तेजपुर) (असम) तक नई बड़ी लाइनः रेल मंत्रालय ने सिलघाट और देकारगांव के बीच एक नई रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित स्टेशन को जोड़ते हुए लगभग 27.50 किलोमीटर की कुल दूरी तय करेगी। प्रस्तावित लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-15 और एनएच-715 के निकट स्थित है, जिससे रेल एवं सड़क परिवहन प्रणालियों के बीच मजबूत तालमेल स्थापित हो सकेगा।

इस नई लाइन के विकास का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना तथा मौजूदा राजमार्गों एवं रेलवे नेटवर्क के बीच एक पूरक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देना है। यह एकीकरण यात्रियों एवं माल के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करेगा, जिससे क्षेत्र में समग्र परिवहन दक्षता में सुधार होगा।

क्षमता वृद्धि परियोजना के लिए डिजाइन की गई प्रस्तावित लाइन, डेकारगांव और न्यू सिलघाट स्टेशनों के बीच मौजूदा रेल अवसंरचना को मजबूत करेगी तथा माल एवं यात्री यातायात दोनों के बढ़ते मांग को पूरा करेगी।

लंबी अवधि में, इस परियोजना से आंशिक आर्थिक वृद्धि एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे असम और इसके आस-पास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बेहतर संपर्क वाले सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को समर्थन मिलेगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

एनएच-65 (महाराष्ट्र) पर ओल्ड पुणे नाका से बोरमणि नाका तक पहुंच मार्ग सहित चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माणः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने महाराष्ट्र के सोलापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-65 पर ओल्ड पुणे नाका से बोरमणि नाका तक लगभग 9.66 किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।

यह परियोजना भारतमाला परियोजना (चरण-क) का हिस्सा है और इसमें अप्रोच रैंप और सर्विस रोड शामिल हैं, जिन्हें क्षेत्र में यातायात प्रवाह और समग्र संपर्क को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार पूरा होने के बदा यह कॉरिडोर शहर के यातायात को सुगम बनाने, यात्रा समय में कमी लाने, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और वाहन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करने वाला एक समर्पित और भीड़-भाड़ मुक्त मार्ग प्रदान करेगा। प्रस्तावित उन्नत गलियारा क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सोलापुर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल मंत्रालय की शहरी गतिशीलता में सुधार एवं सतत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने वाले निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग आधुनिकीकरण एवं क्षमता वृद्धि लक्ष्यों के अनुरूप है। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त सचिव,रसद, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने की।

जेएम और यूएन वूमेन ने सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण निकाय (यूएन वूमेन) ने अनौपचारिक क्षेत्र की महिला उद्यमियों को देश की सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी में सशक्तिकरण और एकीकरण बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता लैंगिक रूप से जिम्मेदार खरीद को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले बिजनेस से ज्यादा सोर्सिंग को बढ़ावा देना शामिल है। इससे व्रीट की वुमनिया पहल के तहत महिला उद्यमियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ सकेगी।

समझौते पर यूएन वूमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती कांता सिंह, और GeM के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अजीत बी. चव्हाण ने हस्ताक्षर किए। GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मिहिर कुमार ने समारोह की अध्यक्षता की। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि यह साझेदारी GeM की उस प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है जिससे GeM के जरिए महिला उद्यमियों की सार्वजनिक खरीद तक पहुँच बढ़ाकर और फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज बनाकर उन्हें मजबूत बनाया जा सके।

GeM केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के लिए राष्ट्रीय सरकारी खरीद पोर्टल है। यह पारदर्शी, दक्ष और समावेशी खरीद को बढ़ावा देता रहता है। GeM के जरिए, महिला उद्यमी और स्व सहायता समूह (SHGs) सीधे सरकारी खरीदारों को अपने उत्पादों की आपूर्ति कर सकते हैं। आसान ऑनबोर्डिंग और खरीद में मदद करने के लिए, GeM ने हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, जूट और कॉयर के सामान, बांस के उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड्स, मसाले, एक्सेसरीज, होम डेकोर और ऑफिस फर्निशिंग को कवर करने वाली जेनेरिक उत्पाद श्रेणी बनाई हैं।

इस समझौते के तहत, यू एन वूमेन प्रशिक्षण सामग्री डिजाइन करेगी, दुनिया भर में सबसे अच्छे तरीकों के बारे में बताएगी, सफलता की कहानियाँ साझा करेगी और महिलाओं के बिजनेस के लिए मान्यता देने की कसौटी बनाने में मदद करेगी। यू एन वूमेन वुमनिया - #VocalForLocal आउटलेट स्टोर को भी प्रमोट करेगी, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों की ऑनबोर्डिंग में मदद करेगी, एमएसएमई उद्यम पंजीकरण को बढ़ावा देगी, महिला प्रशिक्षकों को इकट्ठा करेगी और महिला उद्यमियों को सलाहकारों और संबंधित संस्थानों से जोड़ेगी।

GeM प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा, सरकारी खरीदारों को जागरूक करेगा और महिला उद्यमियों की उपलब्धियों को बताएगा। GeM ऑनबोर्डिंग वर्कशॉप भी आयोजित करेगा, स्थानीय भाषा में ट्रेनिंग मटीरियल बनाएगा और उद्यमिता और अच्छे काम के अवसरों के लिए साझेदार बनाएगा। इसके अलावा, GeM महिला प्रशिक्षकों को जोड़ेगा और महिला उद्यमियों को सरकारी लैब्स और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ जोड़ेगा ताकि उत्पाद विकास, सुधार और बाजार की तैयारी में मदद मिल सके।

GeM और यू एन वूमेन मिलकर लैंगिक रूपसे जिम्मेदार खरीद को बढ़ावा देने, हाइपर-लोकल मार्केट लिंकेज को मजबूत करने और टिकाऊ विकास लक्ष्य गोल 5 - लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने की दिशा में काम करेंगे।

समझौते पर यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस (UNRCO), इंडिया की श्रीमती राधिका कौल बत्रा, दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और लघु उद्योग भारती, PHDCCI, और SEWA भारत जैसे व्यापार संघ के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर समारोह GeM कार्यालय, जीवन भारती बिल्डिंग, नई दिल्ली में हुआ।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ट्रेन में औचक टिकट जाँच, 161 बिना टिकट यात्रिओं से जुमार्ना स्वरुप 50 हजार से अधिक की राशि वसूला

वडोदरा मंडल अपने सम्मानीय यात्रिओं से वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अपील करता है और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर विभिन्न अभियान चलाता है। मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा अहमदाबाद से एकतानगर जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में हाल ही में रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में औचक टिकट जाँच रखी गयी, जिसके अंतर्गत 161 यात्रिओं को बिना टिकट पाया गया और उनसे जुमार्ना स्वरुप 50 हजार से अधिक की राशि वसूल की गयी, जो अब तक की रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जाँच में सबसे अधिक आय है ।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 19 नवंबर, 2025 को अहमदाबाद से एकतानगर जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में यात्रिओं द्वारा अनियमित यानि बिना टिकट यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए वडोदरा मंडल के वाणिज्य बिभाग द्वारा रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में औचक टिकट जाँच रखी गयी। टिकट जाँच दल में वाणिज्य विभाग के मुख्य टिकट इंस्पेक्टर श्री पी के झा, श्री रोशन लाल, श्री एम एस चौहान एवं उप मुख्य टिकट इंस्पेक्टर श्री तेजकरन एवं मुख्य टिकट कलेक्टर श्री ए के सिंह ने भाग लिया और यात्रिओं द्वारा बिना टिकट यात्रा के मामले पकड़े। इस औचक निरीक्षण में 161 यात्रिओं को बिना टिकट पाया गया और उनसे जुमार्ना स्वरुप 50 हजार से अधिक की राशि वसूल की गयी, जो अब तक की रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जाँच में सबसे अधिक आय है ।

ये उपलब्धियाँ पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में गहन टिकट जाँच अभियानों के माध्यम से बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने और यात्री अनुशासन को बढ़ावा देने के वडोदरा मंडल के निरंतर प्रयासों को दशार्ती हैं।

पश्चिम रेलवे ने दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ टिकट जांच प्रदर्शन

मुंबई, पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान टिकट जांच के क्षेत्र में अपना अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त किया है। इस दौरान लगभग 19 लाख बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों का पता लगाते हुए ₹ 121.67 करोड़ की राजस्व-राशि अर्जित की गई। इसमे अनबुक्ड लगेज के प्रकरण भी समाविष्ट हैं। यह उपलब्धि गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त ₹ 80.56 करोड़ की आय की तुलना में 51% की महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करती है तथा यह रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 14% अधिक है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे ने अक्टूबर 2025 में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए ₹ 24 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की है, जो इस अवधि का दूसरा सर्वोत्तम मासिक रिकॉर्ड है। पश्चिम रेलवे का सर्वश्रेष्ठ मासिक रिकॉर्ड मई 2022 में स्थापित हुआ था, जब लगभग ₹ 26 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी।

उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद मंडल ने अक्टूबर 2025 में 50 हजार प्रकरणों का संज्ञान लेकर ₹ 4 करोड़ से अधिक की राशि वसूल कर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ टिकट जांच प्रदर्शन दर्ज किया। इसी क्रम में, मुख्यालय की फ्लाइंग स्क्वॉड ने भी अक्टूबर 2025 में ₹ 2.20 करोड़ का उत्कृष्ट राजस्व अर्जित करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ मासिक रिकॉर्ड स्थापित किया, जो मई 2022 में प्राप्त ₹ 2 करोड़ के पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से अधिक है।

अक्टूबर 2025 के दौरान पश्चिम रेलवे ने कई दैनिक राजस्व उपलब्धियों के नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए। पश्चिम रेलवे द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को लगभग ₹ 1.40 करोड़ की आय अर्जित की गई। इसी प्रकार 18 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद मंडल ने ₹ 38 लाख से अधिक, तथा रतलाम मंडल ने लगभग ₹ 16 लाख का राजस्व प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, 19 अक्टूबर 2025 को मुख्यालय की फ्लाइंग स्क्वॉड ने लगभग ₹ 16.30 लाख की आय दर्ज की।

ये उपलब्धियां पश्चिम रेलवे द्वारा टिकट रहित एवं अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने, यात्री अनुशासन को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित व्यापक टिकट जांच अभियानों की प्रभावशीलता को दशार्ती हैं।

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे की अहमदाबाद एवं वडोदरा क्षेत्राधिकार के माननीय सांसदों के साथ बैठक का आयोजन

पश्चिम रेलवे द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय एवं संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत 21 नवम्बर 2025 को अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों के क्षेत्राधिकार में आने वाले माननीय सांसदों के साथ महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता की एक बैठक का आयोजन अहमदाबाद स्थित सर्किट हाउस में किया जा रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों मंडलों में जारी यात्री सुविधाओं के उन्नयन, चल रही एवं प्रस्तावित परियोजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर सार्थक संवाद स्थापित करना है।

बैठक में अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों में प्रगति पर विभिन्न नवीन यात्री सुविधाओं तथा विकासात्मक उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। इस दौरान प्रजेंटेशन के माध्यम से अहमदाबाद मंडल पर दिवाली एवं छठ पूजा के दौरान किए गए उत्कृष्ट क्राउड मैनेजमेंट प्रयासों, मंडल में प्रगति पर विभिन्न रेल परियोजनाओं—जैसे नई रेल लाइनों, नई ट्रेन सेवाओं, मेजर रिडेवलपमेंट स्टेशनों (भुज, अहमदाबाद, साबरमती) तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए जा रहे अन्य 16 स्टेशनों की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही रेल सुविधाओं, परियोजनाओं, ट्रेनों के नए ठहराव, ट्रेन विस्तार, फेरे बढ़ाने तथा अन्य ढांचागत आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

इस बैठक में माननीय सांसदों में श्री हसमुखभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व), श्री दिनेशभाई मकवाना (अहमदाबाद पश्चिम), श्रीमती शोभनाबेन बारैया (साबरकांठा), श्री भरत सिंहजी डाभी (पाटन), श्री मितेशभाई पटेल (आणंद), श्री जशुभाई राठवा (छोटा उदयपुर), श्रीमती अनिता चौहान (रतलाम), श्री नरहरि अमीन (राज्यसभा) तथा श्री मयंकभाई नायक (राज्यसभा) उपस्थित रहेंगे।

रेलवे प्रशासन की ओर से महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक वडोदरा श्री राजू भडके, पश्चिम रेलवे मुख्यालय से आए प्रमुख मुख्य रेल अधिकारी, फ्छउ तथा दोनों मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

यह पहल जनप्रतिनिधियों के साथ सहभागिता व सहयोग को बढ़ाकर रेल सुविधाओं के उन्नयन, यात्री सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगी।

पश्चिम रेलवे का वसई रोड एवं वैतरणा स्टेशनों के बीच 21/22 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि को रात्रिकालीन ब्लॉक

मुंबई, पश्चिम रेलवे द्वारा रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु शुक्रवार/शनिवार की मध्यरात्रि अर्थात 21/22 नवम्बर, 2025 को वसई रोड एवं वैतरणा स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर छह घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अप फास्ट लाइन पर यह ब्लॉक 23:55 बजे से 02:55 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:30 बजे से 04:30 बजे तक लिया जाएगा। ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 19101 विरार-भरूच मेमू 15 मिनट विलंबित रहेगी और यह विरार स्टेशन से अपने निर्धारित समय 04:35 बजे के स्थान पर 04:50 बजे प्रस्थान करेगी।

इस ब्लॉक के बारे में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है।

अजमेर मण्डल में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेन प्रभावित रहेगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल के मारवाड़ जं.-आउवा स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज नं. 590 किमी 437/4-5 पर आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग हेतु ब्लॉक लिए जाने के कारण कुछ ट्रेन प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

निरस्त ट्रेन

- 23 नवंबर 2025 को जोधपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।
- 24 नवंबर 2025 को साबरमती से चलने वाली ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधुपर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

रेगुलेट ट्रेन

- 22 नवंबर 2025 को ट्रेन संख्या 14701 श्री गंगानगर-बांद्रा टर्मिनस अरावली एक्सप्रेस अजमेर-मारवाड़ के बीच 01.00 घंटा देरी से चलेगी।
- 23 नवंबर 2025 की ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधुपर एक्सप्रेस पालनपुर-मारवाड़ के बीच 25 मिनट देरी से चलेगी।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना, मार्ग और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

माइगॉव के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्विज 2025 के विजेताओं को इसरो, श्रीहरिकोटा में एक प्रेरणादायक यात्रा का अनुभव मिलेगा

(जीएनएस)।

देश के नागरिकों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप, भारत सरकार के नागरिक-सहभागिता मंच, माइजीओवी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में कई पहल कीं। भारत की उल्लेखनीय अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से, माइगॉव ने रचनात्मक प्रतियोगिताओं, सूचनात्मक सोशल मीडिया अभियानों, समाचार पत्रों, ब्लॉग, पॉडकास्ट और वीडियो सहित जन भागीदारी के लिए कई अवसर प्रदान किए।

इन प्रयासों में से एक प्रमुख पहल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रश्नोत्तरी 2025 थी। जिज्ञासा जगाने, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ जन जुड़ाव को गहरा करने के लिए डिजाइन की गई इस प्रश्नोत्तरी में देश भर से हजारों उत्साही प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, माइजीओवी ने शीर्ष 100 विजेताओं को 11 नवंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र - श्रीहरिकोटा रेंज में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का दौरा करने का एक विशेष अवसर प्रदान किया।

इस यात्रा से विजेताओं को भारत के विश्वस्तरीय अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रक्षेपण कार्यों की एक अनूठी, परदे के पीछे की समझ प्रदानकीगई। वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, इस दौरान भारत की अंतरिक्ष यात्रा, प्रमुख उपलब्धियों और अत्याधुनिक तकनीकी विकास पर संवादात्मक सत्र आयोजित किए। निर्देशित दौरे के एक भाग के रूप में, विजेताओं को मास्टर कंट्रोल सेंटर और लॉन्च पैड 1 और 2, उन प्रतिष्ठित प्लेटफार्मों का दौरा करने का सम्मान प्राप्त हुआ, जहाँ से भारत के प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष में जाते हैं। प्रतिभागियों ने रॉकेटों के संयोजन, परीक्षण, परिवहन और प्रक्षेपण के लिए उपयोग किए जाने वाले विशाल बुनियादी ढाँचे का अवलोकन किया—जो मिशन की सफलता सुनिश्चित करने वाली कठोर तैयारी की एक दुर्लभ झलक थी। इस अनुभव को "जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर" बताते हुए, विजेताओं ने इसरो के नवाचार, सटीकता और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति

प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। कई प्रतिभागियों ने बताया कि इस यात्रा ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और अनुसंधान में करियर बनाने के उनके संकल्प को और मजबूत किया।

नवाचार और वैश्विक सहयोग के प्रति इसरो की निरंतर खोज भारत को वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में आकार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यह आदित्य-एल1, गगनयान और आगामी अंतरग्रहीय अन्वेषणों जैसे ऐतिहासिक मिशनों के साथ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई ऊँचाइयों को छू रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रश्नोत्तरी जैसी पहल, वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने और अगली पीढ़ी के नव प्रवर्तकों और अन्वेषकों को पोषित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को और रेखांकित करती है।

2025 की यात्रा, माइजीओवी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी आयोजित करने का तीसरा सफल वर्ष है —जिसकी शुरूआत 2023 में चंद्रयान-3 महा क्विज से हुई, उसके बाद 2024 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रश्नोत्तरी और अब 2025 संस्करण—प्रत्येक वर्ष शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विजेताओं के लिए इसरो परिसर के एक प्रेरक शैक्षिक दौरे के साथ समापन हुआ। इन निरंतर प्रयासों के माध्यम से, माइजीओवी नागरिकों को भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों से जोड़ता रहेगा तथा जिज्ञासा, नवाचार और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देगा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और फ्रांस के आयुध महानिदेशालय ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहयोग बढ़ाने के लिए तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और फ्रांस के आयुध महानिदेशालय (डीजीए) के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहयोग बढ़ाने के लिए तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा विभाग के अनुसंधान एवं विकास सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन डॉ. समीर वी. कामत और फ्रांस के राष्ट्रीय आयुध निदेशक (डीजीए), लेफ्टिनेंट जनरल गेल डियाज डी तुएस्टा ने 20 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भवन में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य भविष्य की रक्षा चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए दोनों देशों/सरकारों की संयुक्त विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाना है। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास में कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परीक्षण गतिविधियों, सूचनाओं के आदान-प्रदान, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन आदि के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करती है।

इस समझौते के तहत, दोनों देशों को उपकरण, तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण लाभ मिलेगा। इस समझौते में उल्लिखित सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में वैमानिकी प्लेटफॉर्म, मानवरहित वाहन, रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत सामग्री, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, नौवहन, उन्नत प्रणोदन, उन्नत सेंसर, क्वांटम प्रौद्योगिकियां, जल के भीतर प्रौद्योगिकियां और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने विश्वास जताया है कि यह सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

26 अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने 'डार्क पैटर्न' को खत्म करने के लिए सेल्फ-ऑडिट के साथ अनुपालन की घोषणा की

(जीएनएस)।

26 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिजिटल मार्केटप्लेस में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, स्वेच्छा से स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत किए हैं, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023 के अनुपालन की पुष्टि करते हैं। यह पहल उपभोक्ताओं को गुमराह करने या हेराफेरी करने वाली भ्रामक ऑनलाइन डिजाइन पर अंकुश लगाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इन प्लेटफार्मों ने डार्क पैटर्न की पहचान करने, इसका आकलन करने और उसे खत्म करने के लिए आंतरिक स्व-लेखा परीक्षा या तृतीय-पक्ष ऑडिट किया है। इन सभी 26 कंपनियों ने घोषणा की है कि उनके प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न से मुक्त हैं और किसी भी तरह के छेड़छाड़ वाले यूजर इंटरफेस डिजाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

उद्योग-व्यापी यह सक्रिय अनुपालन उपभोक्ता पारदर्शिता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता, निष्पक्ष व्यापार नियम और नैतिक डिजिटल इकोसिस्टम को दशार्ता है। यह स्वैच्छिक अनुपाल इस तथ्य को रेखांकित करता है कि उपभोक्ता संरक्षण और व्यावसायिक विकास साथ-साथ चल सकते हैं जिससे ब्रांड विश्वास और दीर्घकालिक विश्वसनीयता मजबूत होती है।

सीसीपीए ने अनुपालन को स्वीकृति देते हुए इसे उद्योग में सर्वोत्तम अभ्यास कहा है

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इन घोषणाओं की सराहना की है। साथ ही अनुकरणीय करार देते हुए अन्य कंपनियों को इसी तरह के स्व-विनियमन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। सीसीपीए ने पहले कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे अपनी वेबसाइटों पर स्व-लेखा घोषणाओं को आसानी से सार्वजनिक पहुंच के लिए प्रमुखता से अपलोड करें।

इन घोषणाओं को सीसीपीए की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है: सीसीपीए अन्य सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों, बाजार इकाइयों, सेवा प्रदाताओं और ऐप डेवलपर्स से आग्रह करता है कि वे इन कंपनियों द्वारा निर्धारित उदाहरण का पालन करें। भारत के डिजिटल क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यवसाय को यह समझना होगा कि भ्रामक जानकारियां देना अदूरदर्शी रणनीतियां हैं जो भविष्य में उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

सोशल मीडिया अभियानों, सूचनात्मक वीडियो और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से नेशनल कंज्यूमर हेल्प लाइन (एनसीएच) ने उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न की पहचान और उनकी जानकारी देने के लिए लोगों को शिक्षित किया है। इस तरह की शिकायतों का व्यवस्थित रूप से समाधान किया जा रहा है और जहां भी आवश्यक हो प्रवर्तन कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। सीसीपीए ने कहा है कि वह संभावित उल्लंघनों पर कड़ी नजर रख रहा है और गलत

भारतीय डाक विभाग ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरे पुनर्निर्मित जेन-जी विषय वाले डाकघर का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

भारतीय डाक ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय डाकघर का उद्घाटन किया, जो जनरेशन जेड के साथ अधिक गहराई से जुड़ने की राष्ट्रव्यापी पहल के अंतर्गत रूपांतरित होने वाला विश्वविद्यालय परिसर का दूसरा डाकघर है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के दृष्टिकोण से निर्देशित इस पहल का उद्देश्य डाकघरों को जीवंत, विद्यार्थी-केंद्रित, प्रौद्योगिकी-सक्षम स्थानों के रूप में फिर से परिकल्पित करना है, जो युवा नागरिकों के साथ प्रतिध्वनित हों।

दिल्ली विश्वविद्यालय डाकघर का प्रवेश द्वार

दिल्ली विश्वविद्यालय डाकघर को मिरांडा हाउस एडवर्सिटी फाइन आर्ट्स सोसाइटी के विद्यार्थी कलाकारों की सक्रिय भागीदारी से नया रूप दिया गया है। इनके विचारों ने भित्तिचित्रों, आंतरिक विषय और प्रचार सामग्री को आकार दिया है, जिससे डाकघर को एक विशिष्ट युवा-केंद्रित पहचान मिली है। मुफ़्त वाई-फाई, समर्पित विद्यार्थी सेवा काउंटर, पार्सल पैकिंग सेवाएँ और रियायती स्पीड पोस्ट दस्तावेज सेवाएँ जैसी आधुनिक सुविधाएँ इस डाकघर को और भी आधुनिक और सुलभ बनाती हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय डाकघर में जेन-जेड के बैठने की जगह

यह परिवर्तन एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 46 वर्तमान डाकघरों को शामिल किया जाएगा, जिनका जनवरी 2026 तक नवीनीकरण किया जाएगा।

डाक विभाग के डाक सेवा बोर्ड के सदस्य (कार्मिक) ने कार्यक्रम में बोलते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समर्थन और सहयोग की सराहना की। इस विद्यार्थी केंद्रित परिवर्तन को साकार करने में उनके प्रोत्साहन और भागीदारी के लिए रजिस्ट्रार, डीन (प्रशासन), प्राचार्य,

कलोल स्टेशन का तेजी से हो रहा है पुनर्विकास

शहर के दोनों छोर और सभी प्लेटफॉर्मों को जोड़ने वाला 40 फीट चौड़े फूट ओवर ब्रिज के निर्माण से यात्रियों की आवाजाही होगी और अधिक सुगम

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के कलोल रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत तेजी से किया जा रहा है। लगभग ₹44.22 करोड़ की लागत से इस स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। पुनर्विकास के अंतर्गत स्टेशन भवन का उन्नयन, नया एंट्री गेट एवं पोर्च, भव्य फसाड, विस्तृत सकुर्लेटिंग एरिया तथा पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। स्टेशन परिसर में सौंदर्यीकरण हेतु आकर्षक भित्तिचित्र भी लगाए जा रहे हैं।

स्टेशन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 70 और 80 वर्ग फीट चौड़े दो नए एंट्री गेट तथा समान आकार के दो निकास द्वार विकसित किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों की आवाजाही और अधिक सुविधाजनक होगी। इसके साथ ही लगभग 14,000 वर्ग फीट का विस्तृत स्टेशन भवन क्षेत्र आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 20,000 वर्ग फीट का कवर शेड तैयार किया जा रहा है, जबकि 2,370 वर्ग फीट का विशाल वेटिंग हॉल यात्रियों को आरामदायक वातावरण प्रदान करेगा।

स्टेशन परिसर में वाहनों की

पार्किंग क्षमता बढ़ाते हुए 18,750 वर्ग फीट में 55 चार पहिया एवं 110 दोपहिया वाहनों के लिए सुसंगठित पार्किंग विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुरक्षित और सहज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगभग 7,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का 40 फीट चौड़ा और 173 लंबा फूट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो शहर के दोनों छोर और सभी प्लेटफॉर्मों को जोड़ते हुए सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म विस्तार, कवर शेड और दूसरे प्रवेश द्वार के विकास का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है।

पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत कई प्रमुख कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पुराने स्टेशन भवन को हटाने के बाद बुकिंग ऑफिस, वेटिंग हॉल एवं पैनल रूम को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। नए मुख्य भवन की नींव, प्रथम एवं द्वितीय मंज़िल का फ्ढउ कार्य पूरा हो चुका है। प्लास्टर, टाइल्स एवं फसाड क्लैडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अन्य फिनिशिंग कार्य जारी हैं। स्काईवॉक एवं लिफ्ट निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।

वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2,000 यात्री कलोल स्टेशन का उपयोग करते हैं और 24 ट्रेनें यहां नियमित रूप से रुकती हैं। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए हाल ही में चार प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें शामिल हैं:

गाड़ी संख्या 20959/60 वलसाड-वडनगर एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 16507/08 जोधपुर-केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 15269/70 मुजफ्फरपुर-साबरमती एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 12215/16 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस

इन चार ट्रेनों के ठहराव से स्थानीय यात्रियों को विभिन्न दिशाओं में यात्रा करने के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे आवागमन और भी सुगम एवं सुविधाजनक होगा। इससे व्यापार, रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

भविष्य की आवश्यकताओं और क्षेत्र की लगातार बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कलोल स्टेशन को प्रतिदिन लगभग 40,000 यात्रियों की आवाजाही को संभालने की क्षमता के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों से न सिर्फ यात्री सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा बल्कि स्थानीय समुदाय को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ भी प्राप्त होगा।

कलोल स्टेशन का यह पुनर्विकास न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि आधुनिक रेल अवसंरचना के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा।

संक्षिप्त समाचार

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह' का आयोजन

ग्रामीण विकास मंत्रालय के पुस्तकालय अनुभाग द्वारा 14 से 20 नवम्बर, 2025 तक 'राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह' मनाया गया। इस दौरान पुस्तकें पढ़ने एवं ज्ञान-साझाकरण की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ठ प्रकाशकों एवं विक्रेताओं द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी, कर्मचारियों द्वारा पुस्तक पहचानो प्रतियोगिता समेत विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने किया।

भारत ने ब्राजील के बेलेम में सीओपी30 के अवसर पर आयोजित आईएसए लीडरशिप सत्र में एसआईडीएस के लिए ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वैश्विक कार्रवाई की अपील की

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सौर ऊर्जा को रूपांतरण और सामाजिक क्रांति के टूल के रूप में रेखांकित किया

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों के साथ सफल रूफटॉप, कृषि और ग्रामीण सौर मॉडल साझा किए

बेलेम/ब्राजील (जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 19.11.2025 को ब्राजील के बेलेम में यूएनएफसीसीसी सीओपी 30 के दौरान आयोजित आईएसए एसआईडीएस प्लेटफॉर्म के उच्च-स्तरीय मंत्रालयी लीडरशिप सत्र को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 'द्वीपों को एकजुट करने, कार्रवाई प्रेरित करने – ऊर्जा सुरक्षा के लिए नेतृत्व' विषय पर आधारित था । इसमें लघु

द्वीपीय विकासशील राज्यों (एसआईडीएस), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के सदस्य देशों और सहयोगी संगठनों के मंत्री तथा वरिष्ठ प्रतिनिधि ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और लचीलेपन के लिए सामूहिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने हेतु एक साथ आए।

सत्र की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि एसआईडीएस को विशिष्ट आयातित निर्बलताओं-जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न व्यवधान और कमजोर अवसंरचना- का सामना करना पड़ रहा है। आईएसए एसआईडीएस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मानकीकृत खरीद, मिश्रित वित्त, स्थानीय क्षमता निर्माण और सौर प्रौद्योगिकियों तक सुव्यवस्थित पहुंच के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने के लिए एक परिवर्तनकारी डिजिटल और वित्तीय इको-सिस्टम का निर्माण करना है।

श्री यादव ने सत्र को संबोधित करते हुए, आईएसए के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के मार्ग को आगे बढ़ाने में एसआईडीएस की सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अपने भाषण की शुरूआत आशावाद के साथ करते हुए, श्री यादव ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा, "आज, भारत ने 500 गीगावाट की संस्थापित बिजली क्षमता को पार कर लिया है – और इसमें से आधे से अधिक स्वच्छ ऊर्जा है।

वित्तीय सेवा विभाग सचिव ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और रिजर्व बैंक के सदस्य मंत्रालयों के साथ अंतर विभागीय समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता की

बैठक में भारत में विदेशी बैंकों की ब्रांच, प्रतिनिधि कार्यालय और सहायक शाखा खोलने पर चर्चा हुई

(जीएनएस)।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, श्री एम. नागराजू ने आज अंतर विभागीय समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और रिजर्व बैंक के सदस्य मंत्रालय शामिल रहे।

अंतर विभागीय समन्वय समिति ने यह बैठक रिजर्व बैंक से मिले प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई थी। ये प्रस्ताव भारत में विदेशी बैंकों की ब्रांच, प्रतिनिधि कार्यालय और सहयोगी शाखाएं खोलने से सम्बंधित थे। इसके साथ ही, समिति ने ऐसे ही प्रबंधों के माध्यम से विदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे भारतीय

बैंकों के प्रस्तावों की भी समीक्षा की।

इसके अलावा, अंतर विभागीय समन्वय समिति ने भारत में अपनी मौजूदा शाखा को दूसरी जगह ले जाने के लिए विदेशी बैंकों की अनुमति मांग पत्र की जांच की। भलीभांति सोच-विचार के बाद, समिति ने प्राप्त प्रस्तावों की सिफारिश की।

अंतर विभागीय समन्वय समिति, वित्तीय सेवाएं विभाग के तहत काम करती है। यह विदेशी और घरेलू दोनों तरह के बैंकों से ऐसे प्रस्तावों की जांच करने के लिए नोडल प्राधिकरण के तौर पर काम करती है। अपनी सिफारिशों पर पहुंचने से पहले, समिति पूरी और आम सहमति पर आधारित तरीका सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग समेत सदस्य मंत्रालयों से सलाह करती है।

ऐतिहासिक उपलब्धिः भारत में जन्मी चीता मुखी ने 5 बच्चों को जन्म दिया

श्री भूपेंद्र यादव ने कहा- भारत में आत्मनिर्भर और जेनेटिकली डायवर्स चीता आबादी बढ़ाने की उम्मीद और मजबूत हुई

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने प्रोजेक्ट चीता के तहत एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट की घोषणा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की गई पोस्ट में, श्री यादव ने कहा कि मुखी — भारत में जन्मी पहली मादा चीता है, इसकी उम्र 2 साल 9 महीने है। मुखी ने पांच बच्चों को जन्म दिया है, जो भारत की चीतों का अस्तिव फिर से स्थापित करने की

पहल की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पल है।

श्री यादव ने बताया कि हाल के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत में जन्मे चीते ने सफलतापूर्वक बच्चे पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना भारतीय वातावरण में इस प्रजाति के अनुकूलन, स्वास्थ्य और लंबे समय तक चलने की मजबूत निशानियों को दिखाती है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा, 'यह बड़ी बात भारत में आत्मनिर्भर और जेनेटिकली अलग-अलग तरह के चीतों की आबादी बढ़ने की उम्मीद को और पक्का करती है,' उन्होंने बताया कि मां और बच्चे ठीक हैं।

श्री यादव ने खुशी के साथ कहा कि यह कामयाबी, भारत के संरक्षण प्रयासों और प्रोजेक्ट चीता के भविष्य की उम्मीदों पर भरोसें को और बढ़ाती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में आयोजित 'नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025' में उद्घाटन भाषण दिया

'वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर' केवल एक थीम नहीं है – यह स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने और भविष्य की महामारियों के खिलाफ तैयारी बढ़ाने के हमारे दृष्टिकोण की नींव है: श्री जेपी नड्डा

"नेशनल वन हेल्थ मिशन संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है"

"संयुक्त प्रकोप जांच और चिकित्सा काउंटरमेजर्स का विकास जारी है, जो हमारी महामारी से लड़ने की तैयारी संबंधी आर्किटेक्चर को मजबूती दे रहा है"

जूनोटिक और जलवायु संबंधी खतरों का सामना करने के लिए सभी क्षेत्रों में एकीकृत और त्वरित प्रतिक्रिया आवश्यक है: डॉ वीके पॉल

"संयुक्त प्रशिक्षण और इकोसिस्टम-व्यापी क्षमता निर्माण के माध्यम से एक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करने की आवश्यकता है"

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और वन हेल्थ पर कार्यकारी संचालन समिति के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन हॉल में एक वीडियो संदेश के जरिये नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 में

उद्घाटन भाषण दिया। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल, वन हेल्थ पर वैज्ञानिक संचालन समिति के अध्यक्ष तथा केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. अजय के. सूद और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल भी उपस्थित थे।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम का विषय है: 'ज्ञान को व्यवहार में लाना – वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर'।

सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने थीम की समयबद्धता को रेखांकित किया, यह देखते हुए की यह समग्र स्वास्थ्य के प्रति देश की बढ़ती प्रतिबद्धता और वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ इसके संरेखण को दर्शाता है। उन्होंने कहा, " 'एक अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर' सिर्फ. एक थीम नहीं है – यह स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य की महामारियों के खिलाफ तैयारी बढ़ाने के लिए हमारे दृष्टिकोण की नींव है।"

पिछले एक दशक में स्वास्थ्य

केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने जयपुर में भूवैज्ञानिक उत्कृष्टता के 175 वर्ष पूरे होने पर जीएसआई के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया

सेमिनार का उद्देश्य भविष्य में भूविज्ञान में सफलताओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता, परिवर्तनकारी विचारों और व्यावहारिक चचाओं को एकीकृत करना है

(जीएनएस)।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज जयपुर में वैश्विक भूवैज्ञानिक संवाद पर आधारित संगोष्ठी का उद्घाटन किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) अपने 175 वें स्थापना वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जयपुर में "अतीत का अन्वेषण, भविष्य का निर्माणः जीएसआई के 175 वर्ष" विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। संगोष्ठी में खान मंत्रालय के सचिव श्री पीयूष गोयल, राजस्थान सरकार के खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी. रविकांत, जीएसआई के महानिदेशक श्री असित साहा, पश्चिमी क्षेत्र के जीएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष श्री

विजय वी. मुगल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह संगोष्ठी ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (बीजीएस), संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) और जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया सहित वैश्विक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठनों के साथ-साथ भारत और विदेशों के प्रमुख भूविज्ञान संस्थानों के प्रख्यात विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है, ताकि विविध तकनीकी सत्रों और अत्याधुनिक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन किया जा सके, वैज्ञानिक आदान-प्रदान को समृद्ध किया जा सके और प्रभावशाली, दूरंदेशी भूवैज्ञानिक चचाओं की नींव रखी जा सके।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने अपने संबोधन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय लचीलेपन में जीएसआई के 175 वर्षों के योगदान की सराहना की। मंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण का विस्तार करने, उन्नत एआई/एमएल-आधारित भू-विज्ञान प्रौद्योगिकियों को अपनाने और भारत के आपदा-तैयारी ढाँचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप, उन्होंने हितधारकों से वैश्विक स्थिरता और साझा वैज्ञानिक प्रगति में योगदान करते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सार्वजनिक इनविट पहल को आगे बढ़ाने के लिए राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरूआत की

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक सार्वजनिक इनविट के रूप में स्थापित करने के लिए प्रक्रिया चला रहा है। सड़क परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को मजबूत करने और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास में निवेश के अवसरों का विस्तार करने की दिशा में इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल के तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रस्तावित इनविट के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरआईआईएमपीएल) को शामिल किया है। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव ने मुंबई में किया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी और सहभागी संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड एक सहयोगी उद्यम है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एनएबीएफआईडी, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व वेंचर्स लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक सहित प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों की इक्विटी भागीदारी है। इस साझेदारी का उद्देश्य मुख्य रूप से खुदरा और घरेलू निवेशकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण क्षमता की जानकारी उपलब्ध कराते हुए एक उच्च-गुणवत्ता वाला, दीर्घकालिक निवेश उत्पाद तैयार करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्य (वित्त), श्री एनआरवीवीएमके राजेंद्र कुमार को निवेश प्रबंधक कंपनी का प्रबंध निदेशक और सीईओ (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस अवसर पर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्री संतोष कुमार यादव ने कहा, " राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण में एक मजबूत कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल के वर्षों में, हमने टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल के माध्यम से 48,995 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों का सफलतापूर्वक मुद्रीकरण किया है और निजी इनविट के चार दौरों में लगभग 43,638 करोड़ रुपये जुटाए हैं, इससे प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आकर्षित हुए हैं। अगले तीन से पांच वर्षों में, लगभग 1,500 किलोमीटर पूर्ण और चालू राष्ट्रीय राजमार्गों को सार्वजनिक इनविट में शामिल किया जाएगा। इससे जनता के लिए निवेश के पर्याप्त अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है कि यह पहल देश में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के निर्माण में जनभागीदारी का एक नया अध्याय लिखेगी।"

राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड सेबी के इनविट नियमों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए, मजबूत शासन मानकों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पारदर्शिता, निवेशक सुरक्षा, साथ ही सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग और अनुपालन ढांचे सुनिश्चित होंगे। खुदरा और सार्वजनिक निवेशकों के लिए इनविट इकाइयों का पहला निर्गम फरवरी 2026 में शुरू होने की आशा है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के 56वें संस्करण की शुरूआत एक ऐतिहासिक रंगारंग परेड के साथ हुई

इफ्फी विश्व भर के नए विचारों, अनूठी कहानियों और क्रिएटिव माइंड्स के परस्पर मिलन का केंद्र है : गोवा के राज्यपाल, श्री पुसापति अशोक गजपति राजू

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सिनेमा अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है: गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

कल्चरल कार्निवल हमारे राज्यों की विविध परंपराओं को प्रदर्शित करता है : डॉ. एल. मुरुगन

दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को सिनेमा में 50 गौरवशाली वर्ष पूरे करने पर सम्मानित किया गया

(जीएनएस)।

आइए... इन सड़कों को अपना मंच बनाइए! जीवन की धुन को महसूस कीजिए! हर गली में एक कहानी को जन्म लेते देखिए! इफ्फी ने गोवा को अद्भुतता के जादू से सराबोर करते हुए, साँस लेती हुई एक जीती-जागती रील में रूपांतरित कर दिया है। अपने गौरवशाली इतिहास में यह पहली बार है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने परंपरा की बंदिशें तोड़कर, सीधे गोवा के उल्लास भरे जीवन में दस्तक दी है—यहाँ के लोगों, गलियों और असीम भावना को गले लगाकर, अब यह एक अद्वितीय और अविस्मरणीय उत्सव बन गया है।

आज अपने भव्य उद्घाटन की एक बोल्ड रीइमेजिनिंग में, इफ्फी-2025 ने

पूरे शहर को एक विशाल, जीवंत कैनवास में बदल दिया—जहाँ सिनेमाई प्रतिभा सांस्कृतिक वैभव के साथ घुलमिल गई और कहानी सुनाने का चिरस्थायी जादू गोवा की सड़कों पर नृत्य कर उठा। जैसे ही कलाकारों, परफॉर्मर्स और सिनेप्रेमियों ने शहर को ऊर्जा और मनोरंजन से भर दिया, गोवा रचनात्मकता के एक धड़कते हुए गलियारे में बदल गया। यह केवल एक महोत्सव की शुरूआत का संकेत नहीं है, बल्कि इफ्फी की विरासत में एक साहसिक नए अध्याय के उदय का भी सूचक है।

महोत्सव का उद्घाटन करते हुए, गोवा के राज्यपाल, श्री पुसापति अशोक गजपति राजू ने इफ्फी के बढ़ते वैश्विक कद की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "इफ्फी रचनात्मक आदान-प्रदान, नए सहयोग और सिनेमाई उत्कृष्टता के उत्सव के लिए एक सार्थक मंच बन गया है। गोवा के कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर, सांस्कृतिक समृद्धि और ग्लोबल कनेक्टिविटी को देखते हुए, यह स्वाभाविक है कि फिल्म प्रेमी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र होते हैं।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इफ्फी ने हमेशा एक पारंपरिक फिल्म महोत्सव की सीमाओं से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव दुनिया भर के विचारों, कहानियों और क्रिएटिव माइंड्स के लिए एक संगम स्थल के रूप में कार्य करता है। इफ्फी युवा फिल्म निमार्ताओं का सहयोग करता है, सिनेमाई प्रतिभा को सम्मानित करता है और फिल्म तथा रचनात्मक उद्योगों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने अपने संबोधन में गोवा के अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ते कद पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "गोवा विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ तैयार है और यही कारण है कि यह इफ्फी का स्थायी स्थान बन गया है। हमारी प्राकृतिक सुंदरता फिल्म निमार्ताओं को आकर्षित करती है, लेकिन हमारे मजबूत नीतिगत सुधार ही उन्हें बार-बार यहां वापस लाते हैं।" उन्होंने कहा कि इफ्फी-2025 'क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का मेल' थीम पर मनाया जा रहा है, जो ग्लोबल क्रिएटिव क्रांति में भारत की लीडरशिप को दिखाता है। इफ्फी भारतीय प्रतिभा को वैश्विक संभावनाओं से जोड़ता है। हमारा सपना गोवा को भारत की 'रचनात्मक राजधानी' बनाना है।

इफ्फी ने अपने 56वें संस्करण में 'द ब्लू ट्रेल' की यात्रा को आगे बढ़ाया

यह फि ल्म एक बुजुर्ग महिला की कहानी है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का अर्थ खोजने के लिए कभी भी देर नहीं होती। — गैब्रियल मास्कारो

मुझे लगता है कि दो-तीन सालों में हमारे पास 1,00,000 लोग होंगे, और हम बहुत जल्द कान महोत्सव जितने बड़े हो जाएँगेः शेखर कपूर

गैब्रियल मास्कारो की डिस्टोपियन फिल्म 'द ब्लू ट्रेल', जिसे पुर्तगाली में 'ओ उल्टीमो अजूल' कहा जाता है, ने आज भारत के 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) की शुरूआत में पहली चमक बिखेरी। गोवा के समुद्री किनारों के बीच शुरू हुए इस महोत्सव में ओपनिंग फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म ने सबके मन में जिज्ञासा और प्रशंसा दोनों पैदा की हैं।

फिल्म के स्क्रीन पर आने से पहले, मारिया एलेजांद्रा रोजास, आटुरी सालाजार आरबी, क्लेरिसा पिनहेइरो, रोजा मालगुएटा और गेब्रियल मस्कारो सहित फिल्म के कलाकार और क्रू ने रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई। एल. मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, संजय जाजू, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और बातचीत सत्र के दौरान आईएफएफआई के महोत्सव निदेशक शेखर कपूर और प्रसिद्ध अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण उपस्थित थे।

फिल्म पर टिप्पणी करते हुए शेखर कपूर ने कहा, "मैंने बर्लिन फिल्म महोत्सव में उद्घाटन फिल्म देखी थी, जहाँ इसे सिल्वर बियर मिला, जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह एक बहुत ही मार्मिक फिल्म है, लेकिन मैं इसके बारे में निर्देशक से ही बात करूँगा।" गेब्रियल मस्कारो ने कहा, "यह फिल्म एक बुजुर्ग महिला के बारे में है जो उम्मीद करती है कि हमें यह समझने में मदद करेगी कि जीवन का अर्थ खोजने का हमेशा समय होता है।" श्री कपूर ने भी आईएफएफआई में अपनी आशा व्यक्त की और कहा, "मुझे लगता है कि दो, तीन साल में हमारे पास 1,00,000 लोग होंगे, और हम बहुत जल्द कान महोत्सव जितने बड़े हो जाएँगे।"

'द ब्लू ट्रेल' के प्रीमियर का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। दर्शकों ने जीवन की चुनौतियों की हृदयस्पर्शी पड़ताल, लचीलेपन के शांत उत्सव और टेरेसा द्वारा साहसपूर्वक की गई आत्म-खोज की चमकदार यात्रा के लिए फिल्म की सराहना की।

एक डायस्टोपियन ड्रामाः

ब्राजील के एक भयावह दृश्य की पृष्ठभूमि पर आधारित, 'द ब्लू ट्रेल' टेरेसा नामक एक 77 वर्षीया महिला की कहानी है, जो भाग्य के कठोर हाथों और सरकार द्वारा उसे एक वृद्धाश्रम में सीमित रखने के दबाव को चुनौती देती है। सपनों से भरे दिल और असीम आत्मा के साथ, वह अमेजन के रास्ते एक साहसिक यात्रा पर निकलती है,

आकाश का स्वाद चखने और पहली बार उड़ान भरने की लालसा में। सामान्य साधनों से रास्ता न मिलने पर, वह नाव से निकल पड़ती है, रास्ते में कई जीवंत किरदारों से मिलती है और उन चुनौतियों का सामना करती है जो उसके साहस की परीक्षा लेती हैं और आश्चर्य जगाती हैं। हर मोड़, ठोकर और जादुई पल के माध्यम से, टेरेसा की यात्रा स्वतंत्रता, लचीलेपन और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के अदम्य आनंद का प्रमाण बन जाती है, जो समाज द्वारा उम्र के लिए निर्धारित सीमाओं से कहीं परे है।

IFFI के बारे में

1952 में स्थापित, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े सिनेमा उत्सव के रूप में प्रतिष्ठित है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और गोवा मनोरंजन सोसायटी (एरऋ), गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, यह महोत्सव एक वैश्विक सिनेमाई शक्ति के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ पुनर्स्थापित क्लासिक फि ल्में साहसिक प्रयोगों से मिलती हैं, और दिग्गज कलाकार पहली बार आने वाले कलाकारों के साथ मंच साझा करते हैं। IFFI को वास्तव में चमकदार बनाने वाला इसका विद्युतीय मिश्रण है- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक प्रदर्शनियाँ, मास्टरक्लास, श्रद्धांजलि और ऊजार्वान वेव्स फिल्म बाजार, जहाँ विचार, सौदे और सहयोग उड़ान भरते हैं। 20 से 28 नवंबर तक गोवा की शानदार तटीय पृष्ठभूमि में आयोजित, 56वाँ संस्करण भाषाओं, शैलियों, नवाचारों और आवाजों की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला का वादा करता है- विश्व मंच पर भारत की रचनात्मक प्रतिभा का एक गहन उत्सव।